PK टाइम्स

दैनिक लोक टुडे

जनता की आवाज...

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com

loktodaynews.com

PK Times News

thepktimesofficial

pk_timesofficial

वर्षः 12 | अंकः 282 | मूल्यः 1.00 रुपए | पृष्ठः 4 | बुधवार, 29 अप्रैल, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

60 से अधिक विधायकों की मांग पर सरकार ने तेज किया मंथन

अब पाकिस्तान नहीं, पश्चिमी राजस्थान में सिंधु का पानी लाने की कवायद शुरू

12 जिलों की प्यास बुझाने के लिए प्री-फिजिबिलिटी स्टडी शुरू

नहरों, सुरंगों और लिंक परियोजनाओं से पेयजल व सिंचाई संकट दूर करने का लक्ष्य

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

पश्चिमी राजस्थान के 12 जिलों तक उत्तरी भारत की नदियों का अतिरिक्त पानी पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। इससे क्षेत्र में पेयजल संकट और खेती-की स्थिति में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। सिंधु जल समझौते के तहत रोके गए उत्तरी भारत के जल को पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हाल ही में मुख्यमंत्री के ओसियां दौरे पर इसे लेकर एक बार फिर मंथन हुआ। अब जल संसाधन विभाग में डीपीआर तैयार करवाने को लेकर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। प्रस्ताव में घग्गर, यमुना, सतलुज, रावी और अन्य नदियों के अतिरिक्त जल को डायवर्ट कर पश्चिमी राजस्थान तक लाने की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कराने की मांग की गई है। साथ ही माही नदी को लूणी से जोड़ने और नर्मदा नहर विस्तार का प्रस्ताव है। पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हो चुकी है। अब पश्चिमी राजस्थान के लिए भी समान दृष्टि से कार्य होना चाहिए। इसको लेकर 60 से ज्यादा विधायकों ने हस्ताक्षर कर अपने पत्र दिए हैं।

घग्गर, यमुना, सतलुज समेत उत्तरी नदियों का अतिरिक्त जल लाने की योजना

एक डब्ल्यूआरसीपी की प्री-फिजिबिलिटी आ चुकी :

जालोर के रास्ते पश्चिमी राजस्थान में गुजरात से पानी लाने के लिए पहले से ही एक डब्ल्यूआरसीपी पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट पर जल संसाधन विभाग ने आपत्ति जताई है। ऐसे में डीपीआर पर काम फिलहाल धीमा है। संभावना है कि डब्ल्यूआरसीपी का यह दूसरा फेज भी प्री-फिजिबिलिटी चरण में जा सकता है।

चरणवार होगा काम :

घग्गर, यमुना, जोजरी व लूणी नदियों के संगम की एक परियोजना बनाकर उसका विस्तार साबरमती लिंक नदी तक किया जा सकता है। पहले चरण में घग्गर नहर परियोजना से वर्षा जल को हनुमानगढ़ जिले से कच्ची नहर बनाकर तथा इंदिरा गांधी व राजीव गांधी लिफ्ट केनाल या अन्य माध्यमों से जोधपुर में जोजरी नदी से मिलाया जा सकता है। दूसरे चरण में यमुना नहर परियोजना के जरिए यमुना से हरियाणा स्थित तेजवाला फीडर से छोड़ा गया वर्षा जल सोनीपत के पास कच्ची नहर बनाकर जोजरी (मीटड़ी) नदी में मिलाया जा सकता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के जिलों में खेती के लिए पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध हो सकेगा। माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने के लिए डीपीआर बनाने को पर्याप्त बजट प्रावधान की मांग की गई है। नर्मदा नहर परियोजना का विस्तार करते हुए इसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर सहित आसपास के अन्य जिलों तक नहरी पानी पहुंचाने की मांग की गई है। डब्ल्यूआरसीपी के सर्वे के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर व बीकानेर तथा जेएनवीयू जोधपुर के भूगोल व भूगर्भ विभागों को शामिल किया जा सकता है।

ये जिले होंगे लाभान्वित :

इस परियोजना के तहत जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को इसका लाभ मिल सकता है।

उच्च स्तर पर मंथन :

जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अरुण कुमार सिडाना ने बताया कि डब्ल्यूआरसीपी की इस मांग पर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। यह एक से अधिक प्रदेशों से जुड़ा मामला है, ऐसे में निर्णय भी वहीं से होगा।

जनप्रतिनिधियों ने की पैरवी

परियोजना के तहत पश्चिमी राजस्थान तक पानी लेन की कवायद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की ओर से मांग के बाद तेज हो गयी है। हाल ही में ओसियां विधायक भैराराम सियोल ने बताया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के मंत्रियों तक मांग रखी गई है।

तकनीकी पक्ष भी रखा गया है। हाल ही ओसिया दौरे के दौरान में मंच से मुख्यमंत्री से इसके लिए आह्वान किया गया। इसके अलावा उत्तरी नदियों का अतिरिक्त पानी लाने के लिए 60 से अधिक विधायकों ने पीएम को पत्र लिखा है।

इस प्रकार है योजना :

तकनीकी ढांचाः सिंधु और उसकी सहायक नदियों (झेलम, चिनाब) के पानी को डायवर्ट करने के लिए 200 किलोमीटर लंबी नहर और 12 सुरंगों के निर्माण का प्रस्ताव है।

उद्देश्यः पाकिस्तान की ओर जाने वाले फालतू पानी को रोककर उसे पंजाब और हरियाणा के रास्ते राजस्थान के पेयजल और सिंचाई संकट को दूर करने के लिए उपयोग करना।

वर्तमान स्थितिः जल संसाधन विभाग द्वारा डीपीआर और प्री-फिजिबिलिटी स्टडी पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श जारी है।

राजस्थान में वन्यजीव गणना 2026 के समय में बदलाव, अब शाम 5 बजे से होगी शुरू

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान में बाघ, बघेरा और अन्य वन्यजीवों की गणना 2026 को लेकर वन विभाग ने अहम संशोधन जारी किया है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक केसीए अरुण प्रसाद द्वारा जारी आदेश में वॉटर होल पद्धति से होने वाली गणना की तिथियों के समय में बदलाव किया गया है।

आदेश के अनुसार अब वन्यजीवों की गणना 01 मई 2026 को शाम 5 बजे से शुरू होकर 02 मई 2026 शाम 5 बजे तक की जाएगी। इससे पहले यह प्रक्रिया 01 मई की सुबह 8 बजे से शुरू होकर 02 मई सुबह 8 बजे तक प्रस्तावित थी, जिसे संशोधित किया गया है। यह गणना प्रदेश के सभी वन सर्किलों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर के साथ-साथ रणथम्भौर, सरिस्का और मुकन्दरा हिल्स बाघ परियोजनाओं में एक साथ की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संशोधित समयानुसार तैयारियां सुनिश्चित करें, जबकि अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकुओं से गोदा

मुंबई में गार्ड्स पर हमला; एटीएस बोली- आईएसआईएस आई के दस्तावेज मिले, अकेले हमला प्लान किया

मुंबई।

मुंबई के मीरा रोड स्थित नया नगर इलाके में एक युवक ने दो सिक्योरिटी गार्ड्स से उनका धर्म पूछने के बाद चाकू से हमला कर दिया। आरोपी की पहचान 31 साल के जैब जुबेर अंसारी के रूप में की गई है। घटना सोमवार सुबह करीब 4 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास दो सिक्योरिटी गार्ड, राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन ड्यूटी पर तैनात थे। आरोपी पहले इलाके में आया और मस्जिद का रास्ता पूछा। कुछ समय बाद वह दोबारा लौटा। उसने एक गार्ड से धर्म पूछने के बाद अचानक चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वह केबिन में घुसा और दूसरे गार्ड से कलमा पढ़ने को कहा। जब गार्ड ऐसा नहीं कर पाया, तो उस पर भी हमला कर दिया गया। दोनों घायल गार्डों को

जुबेर अंसारी, आरोपी

तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र ड्रग्स ने उसके घर से ड्रग्स से जुड़े नोट्स, एक लैपटॉप और कुरान की 3 कॉपियां बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हमला अकेले प्लान किया था।

आरोपी 2020 में अमेरिका से लौटा, कोचिंग देता था

घटना के करीब डेढ़ घंटे भीतर ही नया नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे ठाणे की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

ATS ने बताया कि आरोपी साइंस ग्रेजुएट है और वह 2000 से 2020 तक अपने माता-पिता के साथ अमेरिका में रहा था। अमेरिका में नौकरी नहीं मिलने के कारण वह 2020 में भारत लौट आया। वह 2022 से मीरा रोड स्थित स्मिता रीजेंसी बिल्डिंग में अकेले रहकर ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग देता था।

भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में बंद

मुंबई ।

पश्चिम एशिया तनावों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 416.72 अंकों यानी 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,886.91 पर था, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 97 (0.40 प्रतिशत) अंक गिरकर 23,995.70 पर पहुंच गया।

संपत्ति धोखाधड़ी मामले में सिर्फ खरीदारी ही मुकदमे के लिए काफी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के दशकों पुराने एक जाली वसीयत और संपत्ति धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक खरीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित संपत्ति को किसी कीमती चीज के बदले में सिर्फ खरीद लेना, बिना किसी ठोस सबूत के जो दिखाए कि वह जालसाजी या साजिश में शामिल था, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की एक बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता एस. आनंद के खिलाफ 2004 की एक एफआईआर के संबंध में चल रही कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। इस एफआईआर में करूर जिले में एक वसीयत को जाली बनाने और पुश्तैनी संपत्ति की धोखाधड़ी से बिक्री करने का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि 'सबूत का एक कण भी' ऐसा नहीं था, जिससे संकेत मिले कि अपीलकर्ता ने 12 सितंबर, 1988 की विवादित वसीयत की कथित मनगढ़ंत रचना में कोई भूमिका निभाई थी या खरीद के समय उसे कथित जालसाजी की जानकारी थी।

आरकॉम केस में ईडी ने जब्त की अनिल अंबानी ग्रुप की 3,034 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति

नई दिल्ली।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) बैंक फ्रॉड मामले में 3,034.90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्तियां जब्त (अटैच) की हैं। इससे रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) से जुड़े मामलों में कुल जब्ती 19,344 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। यह जानकारी मंगलवार को जारी जांच एजेंसी के एक बयान में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी विशेष जांच टीम (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रही है। इसमें बैंक और सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है।

गुजरात निकाय चुनाव- सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी जीती

अहमदाबाद में पुलिस-भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प; जडेजा की बहन राजकोट से हारी

अहमदाबाद

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। राज्य के 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। इनमें 9992 सीटें हैं। भाजपा ने अब तक 6161 सीटें जीत

ली हैं। कांग्रेस के खाते में 1315 और अन्य को 592 सीटें मिली हैं। इस चुनाव भाजपा का स्ट्राइक रेट 76% है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसे 380 सीटों पर जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली है। क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की बहन बहन नयनाबा जडेजा राजकोट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गई हैं।

सम्पादकीय ...

आखिर दुनिया का 'थानेदार' ट्रंप और उनका अमेरिका खुद इतना असुरक्षित क्यों है?

अमेरिका लंबे समय से खुद को विश्व नेतृत्व की भूमिका में रखता है। जब कोई देश या नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, तो हर निर्णय पर आलोचना और चुनौती स्वाभाविक होती है–चाहे वह शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था हो या आज की बहुध्रुवीय दुनिया, अमेरिका ने हर चुनौतियों से सीखा और बेहतर समाधान देने की कोशिश की।

आखिर दुनिया का थानेदार कहे जाने वाला अमेरिका खुद असुरक्षित क्यों दिखता है? असल में यह एक मिथक और हकीकत का मिश्रण है। अमेरिका के नेता, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के असुरक्षित दिखने के पीछे कई परतें होती हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी वाले स्थल पर यह तीसरा बड़ा हमला है। इसलिए यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक, संस्थागत और वैश्विक कारणों का मिश्रण है। आइए, इसे सरल तरीके से–ऐसे समझिए।

पहला, वैश्विक नेतृत्व का दबाव- अमेरिका लंबे समय से खुद को विश्व नेतृत्व की भूमिका में रखता है। जब कोई देश या नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, तो हर निर्णय पर आलोचना और चुनौती स्वाभाविक होती है–चाहे वह शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था हो या आज की बहुध्रुवीय दुनिया, अमेरिका ने हर चुनौतियों से सीखा और बेहतर समाधान देने की कोशिश की।

दूसरा, घरेलू राजनीति की तीखी प्रतिस्पर्धा- डॉनल्ड ट्रंप की राजनीति बहुत ध्रुवीकृत रही है। अमेरिका के अंदर ही डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच तीखी टकराहट, मीडिया की आलोचना, और चुनावी दबाव–ये सब किसी भी नेता को रक्षात्मक या असुरक्षित दिखा सकते हैं।

तीसरा, कानूनी और व्यक्तिगत विवाद- ट्रंप कई कानूनी मामलों, जांचों और विवादों से घिरे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नेता अपनी छवि और राजनीतिक भविष्य को लेकर सतर्क–कभी-कभी असुरक्षित–दिख सकता है।

चौथा, बदलती वैश्विक शक्ति-संतुलन- अब दुनिया एकध्रुवीय नहीं रही। चीन, रूस जैसे देश चुनौती दे रहे हैं। इससे अमेरिका की थानेदार वाली स्थिति पहले जैसी निर्विवाद नहीं रही, और यह असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है।

पांचवां, पॉपुलिस्ट (जनप्रिय) राजनीति की शैली-

ट्रंप की राजनीति में हम बनाम वे का नैरेटिव मजबूत रहा है। इस शैली में नेता अक्सर खतरे को बड़ा दिखाते हैं–चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक–ताकि समर्थकों को एकजुट रखा जा सके। इससे भी असुरक्षा का आभास होता है।

छठा, असुरक्षा का एहसास बनाम असली आंकड़े; अमेरिका में लंबे समय में अपराध दर घटी है, खासकर 1990 के बाद से, लेकिन फिर भी लगभग 46प्रतिशत लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी समस्या सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि डर का माहौल भी है कारण स्पष्ट है कि मीडिया, सोशल मीडिया, और मास शूटिंग जैसी घटनाएं लोगों के दिमाग में डर बढ़ाती हैं। सातवां, आर्थिक असमानता- अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देशों में है, लेकिन अमीर–गरीब का अंतर बहुत बड़ा है बेरोजगारी, घर विहीनता, opioid crisis जैसी समस्याएं अपराध को बढ़ाती हैं। जहां असमानता ज्यादा होती है, वहां अपराध और असुरक्षा भी ज्यादा होती है।

आठवां, हथियार संस्कृति: अमेरिका में आम नागरिक के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं। इससे छोटी घटनाएं भी घातक बन सकती हैं, जैसे शूटिंग इंसीडेंट्स। यही कारण है कि हिंसात्मक अपराध का डर ज्यादा रहता है।

नौवां, अपराध का केंद्रित होना: पूरे अमेरिका में समान खतरा नहीं है, बल्कि अपराध कुछ खास शहरों या इलाकों में ज्यादा केंद्रित होता है। इसलिए- कुछ जगह बहुत सुरक्षित है पर कुछ जगह बहुत खतरनाक।

दसवां,, मीडिया और राजनीति का प्रभाव: लगातार चौबीस घण्टे सातों दिन न्यूज और सोशल मीडिया खतरे को अम्प्लीफाय करते हैं। लोग वास्तविकता से ज्यादा डर महसूस करते हैं। अर्थव्यवस्था भी एक फैक्टर है।

ग्यारहवां, पुलिस और सिस्टम की सीमाएँ- अमेरिका पुलिस और जेल पर बहुत खर्च करता है, फिर भी मूल कारणों, जैसे- गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य, नशा आदि पर कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए सुरक्षा का ढांचा प्रतिक्रियावादी है, सुरक्षात्मक/संरक्षात्मक कम। बारहवां, सामाजिक व्यवहार और जीवनशैली- सड़क हादसे, नशा, मानसिक तनाव–ये भी असुरक्षा के बड़े कारण हैं कई मामलों में व्यवहार भी जिम्मेदार है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अमेरिका कमजोर नहीं है, लेकिन: आर्थिक असमानता, हथियार संस्कृति, सामाजिक तनाव और मीडिया द्वारा बढ़ा डर आदि के कारण एक शक्तिशाली देश भी अंदर से असुरक्षित महसूस करता है।

उल्लेखनीय है कि ट्रंप की हालिया सुरक्षा चूक व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर (25 अप्रैल 2026) के दौरान हुई, जब एक संदिग्ध ने होटल में घुसकर गोली चलाई। अमेरिकी अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित समय सारिणी घोषित नहीं की गई है। 25 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में डिनर के दौरान एक संदिग्ध (कोल एलन) ने शॉटगन, पिस्तौल और चाकू लहराते हुए सिक्योरिटी चेकपॉइंट तोड़ा और गोली चलाई। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत नेताओं को सुरक्षित निकाला; एक एजेंट को गोली लगी लेकिन बुलेटप्रूफ वेस्ट से बच गया।

बहरहाल, जांच की स्थिति यह है कि स्नाइपर की एंटी-टेरर यूनिट जांच लीड कर रही है, जिसमें हथियार, गवाह बयान और संदिग्ध के मैनिफेस्टो की पड़ताल शामिल है। एक्टिंग अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि संदिग्ध ट्रंप व उनकी टीम को टारगेट बना रहा था, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहा। ट्रंप ने इसे सिक्योरिटी सक्सेस बताया, पर सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठे हैं।

आखिर जवाब कब? तो अधिकारियों ने लाइव अपडेट दिए हैं, लेकिन सुरक्षा चूक के सवालों (जैसे चेकपॉइंट कैसे टूटा) पर कोई अंतिम रिपोर्ट या सुनवाई की तारीख की घोषणा नहीं हुई। जांच जारी है, अतिरिक्त विवरण आने पर बयान संभव। इससे पहले ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 के हमले (पेंसिल्वेनिया रैली) की जांच में जुलाई 2025 में जारी अमेरिकी सीनेट रिपोर्ट ने सीक्रेट सर्विस की गंभीर चूक उजागर की। यह 2026 की हालिया घटना से जुड़ी नहीं, बल्कि पुरानी घटना पर आधारित है।

मुख्य निष्कर्ष यह है कि विश्वसनीय खुफिया सूचना के बावजूद सीक्रेट सर्विस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की; खतरे को नजरअंदाज किया। वहीं, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय की कमी, खासकर पास की छत को सुरक्षित न करना। संचार, तकनीकी और मानवीय चूकें; कोई बड़ा अधिकारी बर्खास्त नहीं, सिर्फ 6 पर हल्की कार्रवाई।

इसलिए सिफारिशें की गईं कि जिम्मेदारों को दंडित करने, सुरक्षा सुधार और तालमेल मजबूत करने की मांग की। चेयरमैन रैंड पॉल ने इसे पूरी विफलता बताया। सीक्रेट सर्विस ने स्वीकार किया और सुधार शुरू किए। सीक्रेट सर्विस ने 2024 ट्रंप हमले (पेंसिल्वेनिया रैली) की चूक के बाद कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिनमें एजेंटों पर कार्रवाई और प्रक्रियागत बदलाव शामिल हैं। ये कदम सीनेट रिपोर्ट (2025) के बाद तेज हुए। वहीं, एजेंटों पर कार्रवाई हुई। 6 एजेंटों को सस्पेंड किया, 10-42 दिनों की सैलरी कटौती और गैर-ऑपरेशनल पदों पर स्थानांतरित।

वाशिंगटन हिल्टन में इतिहास की पुनरावृत्ति या अमेरिकी लोकतंत्र की कमजोरी?

वाशिंगटन हिल्टन की यह रात केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दर्पण है–जिसमें हम लोकतंत्र की शक्ति और उसकी कमजोरियों दोनों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल कानून और सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे नहीं की जा सकती, बल्कि यह नागरिकों की सोच, उनके व्यवहार और उनके मूल्यों पर भी निर्भर करती है। यदि हम इस संदेश को समझ लें, तो शायद भविष्य में इतिहास को स्वयं को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

प्रियंका सौरभ

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के प्रतिष्ठित वाशिंगटन हिल्टन होटल में शनिवार रात हुई गोलीबारी ने पूरी दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया। यह केवल सुरक्षा संबंधी घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जिसने इतिहास, राजनीति और लोकतंत्र–तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया। व्हाइट हाउस संवाददाता रात्रिभोज के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, तो वहां मौजूद हजारों लोगों के लिए यह किसी भयावह स्वप्न से कम नहीं रहा। इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस जैसे शीर्ष नेता उपस्थित थे। कुछ ही पलों में उत्सव का माहौल भय और अराजकता में बदल गया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की तत्परता ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका उत्तर सरल नहीं है।

इस घटना की सबसे चौंकाने वाली और साथ ही डरावनी बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ। यही होटल, जिसे कभी हिंकली हिल्टन के नाम से भी जाना जाता रहा है, पहले भी अमेरिकी इतिहास की एक बड़ी हिंसक घटना का गवाह रह चुका है। वर्ष 1981 में इसी स्थान के बाहर तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर जॉन हिंकली जूनियर ने गोली चलाई थी। हमले में रीगन गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी को स्थायी रूप से विकलांगता का सामना करना पड़ा । उस समय भी यही सवाल उठे थे–सुरक्षा में चूक कैसे हुई? और आज, लगभग 45 वर्ष बाद, वही प्रश्न फिर हमारे सामने खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दुनिया कहीं अधिक जटिल हो चुकी है और खतरों के स्वरूप भी बदल चुके हैं।

हिल्टन में मौजूद लोगों के अनुसार सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। हंसी-मजाक, भाषण, मीडिया और राजनीति का मिश्रण–यह रात्रिभोज हमेशा से अमेरिकी लोकतंत्र की एक अनूठी परंपरा रहा है। लेकिन अचानक हुई गोलीबारी ने इस परंपरा को झकझोर कर रख दिया। लोग मेजों के नीचे छुप गए। अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण नियंत्रण से बाहर होता प्रतीत हुआ। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई बड़ा जान-माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह घटना केवल एक सुरक्षा चूक नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी समाज में बढ़ते राजनीतिक तनाव का भी संकेत देती है।

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में वैचारिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ा है। 6 जनवरी कैपिटल दंगा जैसी घटनाएं यह दिखा चुकी हैं कि राजनीतिक मतभेद अब केवल बहस और विचार-विमर्श तक सीमित नहीं रह गए हैं। वे सड़कों पर, संस्थानों में और अब उच्च-स्तरीय आयोजनों में भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इस संदर्भ में वाशिंगटन हिल्टन की यह घटना एक अलग घटना नहीं लगती, बल्कि एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा प्रतीत होती है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति भी इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसी नीतियों ने जहां एक बड़े वर्ग को आकर्षित किया, वहीं दूसरी ओर समाज के एक हिस्से में असंतोष और विरोध भी पैदा किया। मीडिया के साथ उनका टकराव, फेक न्यूज जैसे शब्दों का प्रयोग और राजनीतिक विरोधियों के प्रति तीखी भाषा–इन सबने सामाजिक माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया। ऐसे में जब कोई हिंसक घटना घटित होती है, तो वह केवल एक व्यक्ति का कृत्य नहीं प्रतीत होती, बल्कि उस व्यापक सामाजिक और राजनीतिक वातावरण का परिणाम लगती है जिसमें असहमति को अक्सर शत्रुता के रूप में देखा जाने लगा है।

सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को विश्व की सबसे सक्षम सुरक्षा एजेंसियों में गिना जाता है। 1981 की घटना के बाद इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए–अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग, अधिक प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी, और उन्नत निगरानी प्रणाली। फिर भी इस प्रकार की घटना का होना यह दर्शाता है कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों में जोखिम को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। आज के समय में खतरे केवल पारंपरिक हथियारों से नहीं आते, बल्कि वे मानसिक अस्थिरता, ऑनलाइन कट्टरता और व्यक्तिगत निराशा जैसे कारकों से भी जुड़े होते हैं।

इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है – डिजिटल युग और सोशल मीडिया की भूमिका। आज विचारों का प्रसार अत्यंत तेज गति से होता है। गलत जानकारी, षड्यंत्र सिद्धांत और कट्टरपंथी विचारधाराएं कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। जहां 1981 में जॉन हिंकली जूनियर पर फिल्मों के प्रभाव की चर्चा हुई थी, वहीं आज के समय में हमलावरों पर डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया का प्रभाव अधिक देखा जाता है। यह बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है, क्योंकि अब खतरे की पहचान करना और उसे समय रहते रोकना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है।

वैश्विक स्तर पर भी इस घटना के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र माना जाता है, और वहां होने वाली घटनाएं अन्य देशों के लिए संकेत का काम करती हैं। भारत जैसे देशों के लिए जहां बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, यह एक चेतावनी है। केवल तकनीकी रूप से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ-साथ सामाजिक सौहार्द, संवाद और आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देना आवश्यक है।

इस घटना ने एक गहरा प्रश्न भी उठाया है–क्या लोकतंत्र वास्तव में सुरक्षित है? लोकतंत्र केवल चुनाव और संस्थाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जिसमें असहमति को स्वीकार किया जाता है और संवाद को प्राथमिकता दी जाती है। जब समाज में संवाद की जगह टकराव ले लेता है तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है। वाशिंगटन हिल्टन की यह घटना इसी संभावित कमजोरी की ओर संकेत करती है।

इसके सामाजिक निहितार्थ भी अत्यंत गहरे हैं। मीडिया, जो इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र होता है, स्वयं इस घटना का हिस्सा बन गया। पत्रकार, जो सत्ता से प्रश्न पूछने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वहां उपस्थित थे, अचानक स्वयं एक संकट का सामना करने लगे। यह स्थिति हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी भूमिका को लेकर समाज में बढ़ती असहिष्णुता भी इस प्रकार की घटनाओं को जन्म दे रही है।

अंतत:, यह घटना केवल अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, लेकिन हर बार वह एक नया संदेश भी देता है। 1981 की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुए थे। 2026 की इस घटना के बाद संभवत: और व्यापक बदलावों की आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तकनीक या सुरक्षा में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होना चाहिए।

कौन कर रहा है अमेरिकी वैज्ञानिकों का पीछा?

अमेरिका में साल 2023 से संवेदनशील अनुसंधान कार्यक्रम से जुड़े कम से कम 10 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी या राह चलते गायब हो चुके हैं। इनमें से कुछ का तो कत्ल भी किया गया। गायब हो रही देश की बौद्धिक संपदा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, इसका सीधा जवाब किसी के पास भी नहीं है। इनका संबंध अमेरिका न्यूक्लियर और एयरोस्पेस रिसर्च से रहा है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इन घटनाओं के बीच कोई आपसी संबंध है? इस समय एफबीआई जवाब की तलाश में फाइलों की धूल झाड़ रही है। अमेरिकी मीडिया के खुलासे के बाद संघीय एजेंसी ने कहा कि जवाब खोजने के लिए ऊर्जा विभाग, युद्ध विभाग और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर जांच की जा रही है।

सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली हाउस ओवरसाइट कमेटी ने अलग से जांच करने का फैसला लिया है। कमेटी का कहना है कि इन लोगों की पहुंच संवेदनशील वैज्ञानिक जानकारियों तक थी। नासा ने कहा कि मारे गए या गायब हो चुके वैज्ञानिकों के संबंध में संबंधित एजेंसियों के साथ जांच में समन्वय और सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे काफी गंभीर मामला बताया है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के चेयरमैन जेम्स कोमर का मानना है हत्या, मौत या गायब होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। कांग्रेस भी चिंतित है। इस कमेटी के सदस्य डेमोक्रेट जेम्स वॉकिनशॉ ने तो यहां तक कहा है कि इन मामलों के पीछे कोई सुनियोजित साजिश या मकसद छिपा है।

एफबीआई ने 30 जुलाई, 2023 को 59 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाले नासा के वैज्ञानिक माइकल डेविड हिक्स की मौत को भी जांच के दायरे में लिया है। उन्होंने नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) में लगभग 25 साल तक काम किया था। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मुताबिक, लेबोरेटरी में करियर के दौरान उन्होंने धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों पर विशेषज्ञता हासिल की थी। उनकी मौत की वजह का खुलासा नहीं किया गया। उनकी बेटी जूलिया हिक्स यह जानकर हैरत में है कि पिता की मौत पर रहस्य का पर्दा पड़ा है। एजेंसी ने फ्रैंक माइवाल्ड और मोनिका रेजा की मौत के कारणों को भी सामने लाने का फैसला किया है।

कहते हैं कि इसके बाद के सालों में जेपीएल से जुड़े कई और लोग भी मारे गए या लापता हो गए। अंतरिक्ष अनुसंधान के विशेषज्ञ फ्रैंक माइवाल्ड की 2024 में लॉस एंजिल्स में 61 साल की आयु में मौत हो चुकी है। 60 साल की एयरोस्पेस इंजीनियर मोनिका रेजा जून 2025 में लॉस एंजिल्स के एक जंगल में हाइकिंग करते समय लापता हो गई हैं। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने बताया कि रेजा नासा की जेपीएल के मटीरियल्स प्रोसेसिंग ग्रुप की डायरेक्टर थीं। एयर फोर्स के रिटायर्ड मेजर जनरल विलियम नील मैककैसलैंड (68) लापता हैं। उन्हें इसी साल 27 फरवरी को अल्बुकर्क (न्यू मैक्सिको) में अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा गया था। वह अपना फोन, चश्मा और पहनने वाले डिवाइस घर पर ही छोड़ गए थे। मैककैसलैंड पेंटागन के कुछ सबसे उन्नत एयरोस्पेस शोध कार्यों के केंद्र में थे। उन्होंने एक समय राइट पैटर्सन एयर फोर्स बेस स्थित %एयर फोर्स रिसर्च लैबोरेटरी% की कमान भी संभाली थी।

एफबीआई के एजेंट उन्हें सारी दुनिया में तलाश रहे हैं। कहते हैं कि इस बेस पर कथित रोसवेल घटना से जुड़ा किसी बाहरी ग्रह का मलबा रखा है। उनकी पत्नी सुसान मैककैसलैंड विल्करसन ने फेसबुक पोस्ट में माना है कि यह सच है कि नील का यूएफओ समुदाय के साथ कुछ समय के लिए जुड़ाव रहा। यह जुड़ाव किसी के लिए नील को अगवा करने का कारण नहीं हो सकता।

न्यू मेक्सिको के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी से जुड़े दो वैज्ञानिक मेलिसा कैसियस और एंथनी चावेज भी लापता हैं। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस के अनुसार, 53 वर्षीय कैसियस को आखिरी बार जून 2025 में न्यू मैक्सिको के तालपा के पास एक हाईवे पर देखा गया था। वह अपना सामान घर पर ही छोड़ गई थीं और उनका फोन फैक्टरी-रीसेट किया हुआ था। इससे पहले मई में 78 वर्षीय चावेज लापता हो गए थे।

विचार परिवर्तन को तैयार दिखता बंगाल

रामानंद शर्मा

बंगाल सिर्फ वोट नहीं डाल रहा है। वह अपने लोकतांत्रिक भविष्य की नई दिशा भी तय करता दिख रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सघन संशोधन का जो अभियान चलाया, उससे राज्य भर से बड़े पैमाने पर संदिग्ध, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया का सख्त और पारदर्शी होना केवल मतदान तक सीमित नहीं है। यह उस औपचारिक राज्य की वापसी है, जो लंबे समय तक स्थानीय शक्ति संरचनाओं के पीछे छिप गया था। मतदाता परिणाम और सुशासन के आधार पर सत्ता की वैधता तय करना चाहता है।

राजनीति विज्ञान का एक सीधा नियम है कि जहां अनौपचारिक शक्ति संरचनाएं और सिंडिकेट हावी होते हैं, वहां राज्य की औपचारिक क्षमता पूरी तरह कमजोर हो जाती है। यही स्थिति बंगाल में निवेश और विकास की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। जो बंगाल कभी औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, वह आज रोजगार देने में काफी पिछड़ चुका है। जब भी कोई नया कारखाना या उद्यम शुरू होता है, स्थानीय बाहुबली उसमें दखल देते हैं। इससे निवेशक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। जनता अब ऐसा तंत्र चाहती है, जो पारदर्शी हो और औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती दे।

यह चुनाव एक गहरे सामाजिक और पीढ़ीगत बदलाव का भी गवाह बन रहा है। नई पीढ़ी राजनीतिक निष्ठा के बजाय अवसरों के आधार पर प्राथमिकताएं तय कर रही है। आज का युवा मतदाता पारंपरिक झंडों और नारों का मोहताज नहीं है। उसे एक ऐसा तंत्र चाहिए जिस पर वह विश्वास कर सके। वह बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली जैसी सुविधाओं और अवसरों को अपने ही राज्य में देखना चाहता है। जब यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो उसका गुस्सा सत्ता के खिलाफ मुखर होता है। राष्ट्रवाद, पारदर्शिता और विकास की राजनीति का जो नया विकल्प राज्य में उभर रहा है, वह इसी युवा वर्ग की आकांक्षाओं को स्वर देता दिख रहा है। राजनीति में नागरिक और सरकार के रिश्ते के मायने भी तेजी से बदल रहे हैं।

सरकार की मुफ्त राशन और नकद सहायता जैसी योजनाओं ने समाज के निचले तबके को फौरी राहत जरूर दी है, लेकिन अर्थशास्त्र और राजनीति का यह अनुभव बताता है कि एक सीमा के बाद कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव घटने लगता है। खासकर तब, जब वे जनता की नई आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पातीं। जब सरकार नागरिकों को स्थायी रूप से केवल 'लाभार्थी' मानकर चलने लगती है तो बुनियादी विकास पीछे छूट जाता है। यह निर्भरता समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। बंगाल का मतदाता अब कुछ सौ रुपयों की मासिक सहायता से आगे पक्का रोजगार और अपनी मेहनत का सम्मानजनक मोल चाहता है। सशक्तीकरण का यही माडल अब बंगाल के विमर्श में जगह बनाता प्रतीत हो रहा है।

जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी चिंताएं बन चुकी हैं, जिन्हें अब किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ के आरोप और उनसे जुड़ी चिंताओं ने राज्य की सामाजिक पहचान पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। संदेशखाली जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सत्ता के करीब माने जाने वाले स्थानीय बाहुबलियों ने जिस प्रकार महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई, उसने बंगाली भद्रलोक और ग्रामीण समाज को भीतर तक आहत किया। यह एक विशेष प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा नतीजा है। राज्य का एक वर्ग कह रहा है कि इस तरह की नीतियों में कानून के समान शासन की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। उत्तर बंगाल के राजबंशी समुदाय से लेकर मतुआ समाज तक, सभी अपनी अस्मिता और अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति में लंबे अरसे तक राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल अपना दबदबा बनाए रखने के हथियार के रूप में हुआ है। चुनाव से पहले लोगों को डराना और विरोधियों को निशाना बनाना यहां का कड़वा सच रहा है, लेकिन इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भारी तैनाती और चुनाव आयोग के सख्त रवैये ने डर के उस माहौल को काफी हद तक खत्म कर दिया है।

इसी सुरक्षित माहौल में बंगाल में एक मौन मतदाता उभर रहा है। यह वह मतदाता है, जो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन मतदान केंद्र पर अपनी स्वतंत्र पसंद दर्ज करता है। बिना किसी डर या दबाव के मतदान करने की यह हिम्मत एक परिपक्व होते लोकतंत्र का बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की धरती पर चल रहा यह मंथन केवल एक सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन की पदचाप है।

प्रशिक्षण महाभियान भाजपा का एक प्रमुख वैचारिक और संगठनात्मक कौशल विकास कार्यक्रम, इसमें कार्यकर्ताओं को 'एकात्म मानववाद' अंत्योदय' के सिद्धांतों में करता है प्रशिक्षित:– वीडी शर्मा

प्रशिक्षण का दायरा बहुत बड़ा, इसे समझने की जरूरत, प्रशिक्षण से आने वाली नई पीढ़ी को सिखने को मिलेगा: भजनलाल शर्मा

प्रशिक्षण तरासने की प्रक्रिया, जो सीखता है वह बढ़ता है, जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी कर देता है बंद:– मदन राठौड़

जयपुर

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार से 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026' का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महाभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं सांसद वीडी शर्मा ने जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 भाजपा का एक प्रमुख वैचारिक और संगठनात्मक कौशल विकास कार्यक्रम है, जो बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कार्यकर्ताओं को 'एकात्म मानववाद' और 'अंत्योदय' के सिद्धांतों में प्रशिक्षित करता है। इसका उद्देश्य पार्टी विचारधारा को मजबूत करना, कार्यपद्धति में निखार लाना और डिजिटल माध्यमों से कार्यकर्ताओं को आधुनिक बनाना है।

महाभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण महाभियान में कार्यकर्ताओं में सेवा, समर्पण की भावना विकसित करना और उन्हें संगठनात्मक चुनौतियों के लिए तैयार करना। यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के दर्शन पर केंद्रित है। इस महाअभियान में मंडल, जिला और प्रदेश स्तरों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व क्षमता बढ़ाना और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना है।

प्रशिक्षण महाभियान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रशिक्षण तरासने की प्रक्रिया है। जो सीखता है वह बढ़ता है, जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण से ही संगठन का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण महाभियान 2026 में पार्टी ने एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, जो डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप है। इसमें मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता भाग लेते हैं। प्रशिक्षण की शुभारंभ आज से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला से हुआ है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान को संगठन सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं को विचार, व्यवहार और नेतृत्व तीनों स्तरों पर समृद्ध करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और एकात्म मानववाद का दर्शन ही भाजपा की कार्यसंस्कृति की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि कार्यकर्ता के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। इससे संगठन की कार्यपद्धति में एकरूपता आएगी और सेवा, समर्पण तथा राष्ट्रहित की भावना और अधिक प्रखर होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह महाअभियान भाजपा को बूथ स्तर तक और अधिक संगठित, सक्रिय और प्रभावी बनाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण का दायरा बहुत बडा है, इसे समझने की जरूरत है। प्रशिक्षण से आगे आने वाली नई पीढ़ी को सिखने को मिलता है। हमारा कार्यकर्ता हमारी धरोवर है, हमारे कार्यकर्ता के व्यवहार को जमीनी स्तर पर हर कोई देखता है। पार्टी हमेशा एक ही बात कहती है आप कर्म करें, बाकि मेरे पर छोड़ दें। कार्यकर्ताओं को कभी अपना वजन कम नहीं आंकना चाहिए। हमें जनता के बीच पॉजिटिव नेरेटिव बनाना है। इसके लिए सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाने का कार्य आप सभी कार्यकर्ताओं को करना होगा। हमारी सरकार के 2 साल बनाम 5 साल के कार्यों को जमीन पर लेकर जाना होगा। फिर चाहे ईआरसीपी योजना, देवास योजना, यमुना जल समझौता हो या फिर मेट्रो, रिंग रोड योजना सहित अन्य योजनाएं कार्यकर्ताओं को इन्हें जन जन तक पहुंचाना है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का राज घोटालों भरा रहा। कांग्रेस ने जेजेएम में घोटाला किया, हमने केंद्र से आग्रह किया तो जेजेएम को 2028 तक बढ़ाया और घर घर जल पहुँचा रहे है। कांग्रेस ने प्रदेश को गर्त में पहुँचाया, जहां पिछली सरकार में 1 लाख 67 हजार प्रतिव्यक्ति आय थी ,हमने कठोर परिश्रम करके प्रदेश में 2 लाख 5 हजार प्रतिव्यक्ति आय पहुंची दी। हमने 21.15' ग्रोथ की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण ही हमारी पार्टी को अन्य दलों से अलग बनाता है। एक समय था जब विपक्ष पंचायत से पार्लियामेंट तक था, लेकिन आज कहा पहुंच गया, सबके सामने है। इसका मुख्य कारण उस संगठन में प्रशिक्षण अभियान की कमी, संगठन की रीति और नीति का अभाव है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अपने कार्य को हथियार बना लो, पार्टी आप को मौका अवश्य देगी। कार्यकर्ताओं को कार्य देना और उसका परिणाम लेना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें सभी कार्यकर्ताओं को समान व्यवहार के साथ कार्य का बंटवारा करना चाहिए। इस दौरान मंच पर प्रदेश उपाध्यक्ष ?ज्योति मिर्धा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, भूपेंद्र सैनी, कैलाश मेघावल, प्रशिक्षण महाभियान में प्रशिक्षण के प्रदेश संयोजक मिथिलेश गौतम, सह संयोजक मनीष पारीक, जगदीश धानदिया, महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी संतोष अहलावत उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण महाभियान को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण हमारी ताकत है, हमारे कार्यकलाप, विचारधारा ही प्रशिक्षण का आधार है। हम पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और ?अंत में स्वयं के लिए कार्य करते है। हमारा प्रशिक्षण के प्रति समर्पण, कार्यकर्ताओं के प्रति हमारा समर्पण ही हमारी नई पीढ़ी का अनुसरण करता है। हम क्रियाकलाप के माध्यम से आने वाली पीढी को सिखाते है। हमारी बैठकें भी प्रशिक्षण का केंद्र होती है। हमारे कार्यकर्ताओं को अनुशासन के साथ हमारी पार्टी की रीति और नीति सीखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि संगठन की नजर प्रत्येक कार्यकर्ता पर है, वे ये ना सोचे की उन्हें कौन देख रहा है।

200 शहरों का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत, अब केंद्र देगा 2,341 करोड़

प्रदेश के विभिन्न शहरों में 363 परियोजना पर चल रहा काम, विकास कार्य से बदलेगी शहरों की सूरत

लोक टुडे। जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 11 हजार 560 करोड़ रुपए की राशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

अमृत 2.0 के तहत चल रही इन परियोजनाओं में 5 हजार 950 करोड़ रुपए की सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, 5 हजार 99 करोड़ रुपए लागत की जलापूर्ति परियोजनाएं और 505 करोड़ रुपए की जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं शामिल हैं।

जयपुर में 2624 करोड़ की परियोजनाएं प्रगतिरत :

जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क की मरम्मत और नए क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने के 600 करोड़ रुपए के काम की डीपीआर तैयार की जा रही है जबकि 731 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है। इसी तरह, हेरिटेज निगम क्षेत्र में एसटीपी निर्माण और अपग्रेडेशन, सीवर लाइनों की मरम्मत, पुरानी सीवर लाइनें बदलने और नई सीवर लाइनें बिछाने के 1040 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के अनुबन्ध जारी कर काम करवाया जा रहा है। जलापूर्ति वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के 253 करोड़ रुपए की परियोजना की एनआईटी जारी की जा चुकी है। इस तरह, जयपुर शहर में केन्द्र प्रवर्तित इस योजना के अंतर्गत 2 हजार 624 करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। जोधपुर शहर में अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 731 करोड़ रुपए के एसटीपी और सीवरेज लाइन मरम्मत एवं नई सीवर लाइनें बिछाने के कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 725 करोड़ रुपए के जलापूर्ति एवं सीवरेज कार्य प्रगतिरत हैं। इसी तरह कोटा शहर में 700.87 करोड़, उदयपुर में 420.92 करोड़, सीकर में 404 करोड़ रुपए, भीलवाड़ा में 360.94 करोड़, भरतपुर में 299.95 करोड़, अजमेर में 396 करोड़, अलवर में 294.46 करोड़ एवं भिवाड़ी में 276.59 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के कार्य करवाए जा रहे हैं।

जलाशयों को मिल रही नई जिंदगी :

अमृत 2.0 में जलाशय पुनरुद्धार की 134 परियोजनाओं पर 505 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। इनका उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक बावड़ियों, झीलों और तालाबों का पुनरुद्धार करना है, जो विरासत पर्यटन और भूजल पुनर्भरण दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सुमेरपुर (पाली) में 23 करोड़ रुपए की लागत से वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और उपचारित जल को जवाई नई में प्रवाहित करने की परियोजना, सिंहप्रस्थ सरोवर के पुनरुद्धार एवं विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। नाथद्वारा में 17.3 करोड़ रुपए की लागत से सिहाड़ और नाथूवास तालाब, बांसवाड़ा में 6.77 करोड़ रुपए से नाथेलाव और डायलाब तालाब के काम शुरू करवाए जा रहे हैं।

हथियार दिखाकर घर में घुसा बदमाश, बेहोश कर हाथ-पैर बांध दिए थे

जयपुर में बंधक बनाकर रिटायर्ड कर्नल से 2.20 लाख लूटे

जयपुर।

जयपुर में एक रिटायर्ड कर्नल को बंधक बनाकर 2.20 लाख रुपए लूट लिया। हथियार दिखाकर घर में घुसे नकाबपोश बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग को बेहोश कर हाथ-पैर और मुंह बांधकर बदमाश ने बेड पर पटक दिया था। बगरू थाना पुलिस में पीड़ित बुजुर्ग ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बदमाश की तलाश शुरू कर दी।

डीसीपी (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया- बगरू के ओमेक्स सिटी निवासी 71 वर्षीय रिटायर्ड कर्नल के साथ रविवार दोपहर 1:30 बजे लूट की वारदात हुई। वे घर पर अकेले टीवी देख रहे थे। इस दौरान एक लड़का गेट खोलकर अंदर आया। बदमाश के हाथ में चाकू और पेंट में पिस्टल रखी थी। घर में घुसे बदमाश ने हेलमेट लगा रखा था, उसने धमकी देते हुए रुपए मांगे। रुपए नहीं होने की कहने पर बदमाश ने मोबाइल छीनकर तोड़ दिया।

बेहोश होने पर बनाया बंधक

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बदमाश ने जेब से कुछ निकालकर उन्हें सुंघाया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में बदमाश ने मेरे हाथ-पैर और मुंह बांध दिए। इसके बाद कमरे के ऊपर वाली रैक में रखे 2.20 लाख रुपए निकाले। बदमाश ने बैग में रुपए रखकर फरार हो गया।

ढाई घंटे बाद आया होश, 45 मिनट में खुद को खोला

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि करीब ढाई घंटे बाद होश आया। शाम करीब 4 बजे होश आने पर खुद के हाथ-पैर और मुंह बंधा होना पाया। कमरे में देखने पर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बेड पर मैं बंधक की हालत में पड़ा था।

होश आने के बाद मैंने शोर मचाकर लोगों को बुलाने की कोशिश की। मुंह बंद होने के कारण मेरी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा सकी।

उन्होंने बताया- जैसे-तैसे मशक्कत कर खुद को बंधन मुक्त करने की कोशिश शुरू की। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद खुद के हाथ-पैर और मुंह को बंधन से खोल सका। इसके बाद रैक में रखे रुपए देखे तो गायब मिले। आस-पड़ोसियों को वारदात के बारे में बताकर बगरू थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस वारदातस्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ बदमाश की तलाश कर रही है।

अब कोई नहीं रहेगा अनभिज्ञ : ग्राम रथों से जगेगी जागरूकता की अलख, 15 दिन तक हर पंचायत में पहुंचेगी 'सरकार'

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने ग्राम रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

लोक टुडे। जयपुर

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव गांव तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ग्राम रथ अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ मंगलवार को सिरोही जिला कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सिरोही जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित, जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक जगसीराम कोली, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राजेश गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद अग्रवाल, सीओ मुकेश चैधरी, एसीईओ शैलेन्द्र जोशी, गणपतसिंह, महिपाल चारण सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अभियान संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने बताया कि ग्राम रथ अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं पशुपालकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत करना तथा वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार करना हैं। इन रथों के माध्यम से प्रत्येक पात्र तक योजनाओं की जानकारी पहुचेंगी और अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पहुचेगा। अभियान के शुभारंभ समारोह में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई जिसमें राज्य सरकार के द्वारा दो साल में किए गए कार्यों के बारे में बताया गया।

तीनों विधानसभा क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में करेंगे प्रचार :

अभियान के तहत सिरोही जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों सिरोही शिवगंज, आबू पिंडवाड़ा और रेवदर की ग्राम पंचायतों में ग्राम रथ संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक रथ प्रतिदिन 4 से 5 स्थानों पर पहुंचकर ऑडियो-वीडियो माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेगा।

13 विभागों की योजनाओं का समावेश :

ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास सहित 13 विभागों की योजनाओं, उपलब्धियों एवं नवाचारों की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रचार सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्यमंत्री के संदेश का किया जाएगा प्रसारण :

अभियान के दौरान ग्राम रथों में स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश एवं संवाद प्रसारित किया जाएगा। अभियान के सफल संचालन के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी तथा संबंधित उपखंड अधिकारियों को विधानसभा स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे अभियान की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

सुझाव पेटिका से मिलेगा जन-फीडबैक :

ग्राम रथों में सुझाव पेटिका की व्यवस्था भी की गई है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों के सुझाव एकत्रित कर राज्य सरकार तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में और सुधार किया जा सके। अभियान के दौरान स्थानीय कलाकारों के कला जत्थों द्वारा संध्या चैपाल के माध्यम से लोक शैली में योजनाओं एवं 'ग्राम' आयोजन का आकर्षक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का गहलोत पर तंज- 'पायलट अब भी उनकी नजर में बच्चे', सियासी गलियारों में हलचल

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 'पायलट-गहलोत' विवाद में एंट्री मारते हुए बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। राठौड़ ने तंज कसा कि गहलोत आज भी पायलट को 'बच्चा' समझते हैं। राजस्थान की राजनीति में बयानों का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के 'बहरूपिया' वाले बयान पर जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का बचाव किया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा इसका जवाब इतने आक्रामक अंदाज में देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को जयपुर में मोर्चा संभालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'अपनत्व' पर ही सवाल खड़े कर दिए। राठौड़ ने गहलोत के बयान का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए इसे पायलट का अपमान करार दिया और यहाँ तक कह दिया कि भाजपा जितना प्रचार इन दोनों नेताओं का कर रही है, उतना तो वे खुद भी नहीं करते।

गहलोत के मन में मैल, पूरे पायलट को कांग्रेस में क्यों नहीं बताया? :

मदन राठौड़ ने गहलोत के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 'पायलट की दोनों टांगें अब कांग्रेस में हैं'। राठौड़ ने चुटकी लेते हुए कहा कि गहलोत साहब ने सिर्फ टांगों की बात की, पूरे सचिन पायलट की नहीं। इससे साफ पता चलता है कि उनके मन में अभी भी कितना मैल भरा हुआ है। प्रभारी के विवादित बयान का बचाव करते हुए राठौड़ ने एक नया एंगल दिया। उन्होंने कहा कि पायलट सुंदर और सौम्य हैं, लेकिन उनके 'रूप' अलग-अलग हैं।

इधर, पायलट समर्थकों में बयान पर गुस्सा :

कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने भाजपा प्रदेश प्रभारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आपको औकात से ज्यादा चूं चपड़ नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट के बारे बोलने से पहले ज़रा पांडाल में भीड़ तो देख लेना चाहिए। ये हालत तब है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अमला, पुलिस मशीनरी और पूरा संगठन झोंक देने के बाद भी मुश्किल से 500 लोग जुट नहीं पाए। ऊपर से प्रभारी के भाषण का ऐसा निम्न स्तर की मुद्दों से ज्यादा हताशा झलक रही थी। राजनीति में विरोध हो सकता है, वैमनस्य नहीं। व्यक्तिगत अपमान और मर्यादा भंग करना भाजपा की आदत बन गई है। बीजेपी लगातार शुचिता और लोकतांत्रिक संस्कारों को खत्म करने पर आमादा दिख रही है। भाजपा नेतृत्व को अपने नेताओं और पदाधिकारियों के आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अजयपाल को पुलिस ऑब्जर्वर बनाए जाने पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल

लोक टुडे। जयपुर/कोलकत्ता

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की नियुक्ति को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। चुनाव ड्यूटी के दौरान उन्हें पुलिस ऑब्जर्वर बनाए जाने पर विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। पार्टी ने अजय पाल शर्मा पर भाजपा से करीबी संबंध होने का आरोप लगाते हुए उन्हें 'भाजपा एजेंट' तक करार दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने कहा कि शर्मा का सेवा रिकॉर्ड विवादों से घिरा रहा है और उनके खिलाफ कई एनकाउंटर के मामले सामने आ चुके हैं। वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि अजय पाल शर्मा खुद को 'सिंघम' की छवि में पेश करते हैं और सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं। साथ ही उन्होंने आईपीएस और डीएसपी स्तर की पोस्टिंग में पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की ओर से पक्षपातपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में तनाव और बढ़ गया है, वहीं चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी बहस तेज हो गई है।

जयपुर का नया रेलवे हब : 205 करोड़ से संवरेगा खातीपुरा स्टेशन, बनेगा वर्ल्ड क्लास मेगा टर्मिनल

प्रमोद कुमार। जयपुर

राजधानी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में खातीपुरा स्टेशन को एक बड़े मेगा टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में जयपुर जंक्शन का मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। यहां ट्रेनों की हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइनें, वॉशिंग पिट, ऑटोमैटिक कोच वाशिंग प्लांट और अत्याधुनिक मेंटेनेंस सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। करीब 205 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे कोच केयर कॉम्प्लेक्स में वंदे भारत, एलएचबी और डीएमयू जैसी विभिन्न श्रेणियों के रेक का एक ही स्थान पर रखरखाव संभव होगा। स्टेशन पर 6 हाई लेवल प्लेटफॉर्म और 8 लाइनें यात्रियों को बेहतर सुविधा देंगी। वहीं अलग-अलग मेंटेनेंस, शंटिंग और रिपेयर कार्यों के लिए दर्जनों नई लाइनें भी विकसित की जा रही हैं। दिल्ली कॉरिडोर समेत लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं भी इससे बढ़ेंगी।

रेलवे संचालन और अधिक सुगम बनेगा :

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि खातीपुरा को सैटेलाइट टर्मिनल के रूप में विकसित करने से जयपुर जंक्शन पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा और शहर में रेलवे संचालन अधिक व्यवस्थित और सुगम बन सकेगा।

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने किया 181 हेल्पलाइन केंद्र का निरीक्षण

जयपुर

राज्य में सुशासन और अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा द्वारा मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र' का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि एक प्रकरण को सुनकर केस-स्टडी के माध्यम से समाधान प्रक्रिया की गुणवत्ता की भी जांच की।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायतों की प्रगति एवं निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को बेहतर एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के उपरांत मुख्य सचिव ने संदेश पट्ट पर अपने संदेश में लिखा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यक्षमता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे 'देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली' (द्धठ्ठस्रद्धड्ढ'द्य द्बद्गह्यह्ल ह्लद्धद्ग1ड्ढठ्ठष्द्ध ह्लद्धह्यह्लद्धद्गह्य-ह्युड्ढ्य ह्य4ह्यद्दद्ध) के रूप में प्रमाणित किया।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के पंजीकरण से लेकर उनके तार्किक निस्तारण तक की यह डिजिटल यात्रा अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। वहीं, पुलिस महानिदेशक ने केंद्र में शिकायतों की लाइव सुनवाई का अनुभव लिया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि, 'हेल्पलाइन केंद्र का यह भ्रमण एक 'आई-ओपनर' और अत्यंत समृद्ध अनुभव रहा। सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में यह प्रणाली मील का पत्थर साबित हो रही है।' निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने जयपुर ग्रामीण के फागी वृत्त के एक प्रकरण में परिवादी हेमराज बुनकर से वार्ता की। इस प्रकरण में परिवादी द्वारा रेनवाल मांझी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराई गई थी। उक्त शिकायत के क्रम में वृत्ताधिकारी, द्वारा राजस्थान संपर्क में लिखित जवाब में अवगत कराया गया कि उक्त दिनांक को ही परिवाद दर्ज कर लिया गया था तथा इस केस पर अनुसंधान जारी है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक ने निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाले परिवादों का सही श्रेणीकरण, सटीक सब्जेक्ट रिवीजन एवं उचित लेवल मैपिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान हो सके।

आसमान में 45-मिनट तक सांसत में रही पैसेंजर्स की जान

फ्लाइट ने लगाए 8 चक्कर; रनवे को टच कर फिर उड़ा विमान

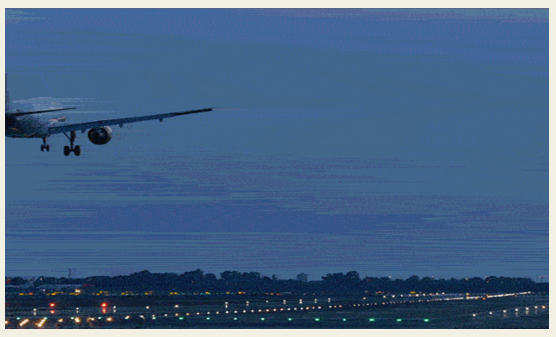

जयपुर।

खराब मौसम के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार रात फ्लाइट संचालन काफी प्रभावित हुआ। आंधी और कम विजिबिलिटी की वजह से कई विमानों की लैंडिंग नहीं हो सकी। तीन फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा, वहीं कई फ्लाइट्स काफी समय तक आसमान में होल्ड पर रहीं। आबूधाबी से आने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट समय पर लैंड नहीं कर सकी। फ्लाइट शाम 7:35 बजे जयपुर पहुंची थी। लेकिन तेज हवा और खराब विजिबिलिटी के चलते उसे तुरंत लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। विमान करीब 45 मिनट तक आसमान में होल्ड पर रहा। इस दौरान उसने करीब आठ चक्कर लगाए। मौसम में हल्का सुधार होने पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई।

आसमान में चक्कर लगाते रहे विमान

मुंबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट छ्ङ-1219 जयपुर में लैंड नहीं कर सकी। इसे रात 10:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरना था। आंधी के कारण पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हुई। विमान काफी देर तक आसमान में चक्कर लगाता रहा। बाद में इसे दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया। इसी तरह अहमदाबाद से रात 9:12 बजे रवाना हुई इंडिगो की फ्लाइट 6 ई -7131 रात 10:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होनी थी। आंधी की वजह से काफी देर तक फ्लाइट को जयपुर एयरस्पेस में होल्ड पर रखा गया। परिस्थितियां सामान्य नहीं होने पर इसे दिल्ली डायवर्ट कर दिया गया।

विभागीय वेबसाइट-सोशल मीडिया से डाटा लेकर अफसरों-कर्मचारियों से ठगी

जयपुर।

सोशल मीडिया पर कर्मचारी के पास अफसर की प्रोफाइल फोटो लगे नंबर से मैसेज आता है- 'मैं मीटिंग में हूं। कॉल नहीं ले सकता। तुरंत कुछ रुपए या गिफ्ट वाउचर भेज दो।' बड़े अधिकारी की प्रोफाइल फोटो, आदेश और इमरजेंसी स्थिति देखते हुए कर्मचारी बिना सोचे-समझे रुपए ट्रांसफर कर देता है। बाद में पता चलता है कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुका है। प्रदेश में इसी तरह 'पहचान चोरी' के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

इस पर पुलिस ने लोगों को सचेत रहने की एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा- साइबर ठग सोशल मीडिया या सरकारी विभागीय वेबसाइट से डाटा लेकर ठगी कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने विशेष एडवाइजरी जारी कर आम लोगों और कर्मचारियों को सतर्क रहने की अपील की है। एडीजी साइबर क्राइम वी.के. सिंह के निर्देश पर जारी चेतावनी में बताया गया कि अपराधी अब अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग कर डिजिटल ठगी कर रहे हैं।

राजस्थान आईएसीसी चैप्टर, इंडो- यूएस ट्रेड इन्वेस्टमेंट और टेक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगा :दिया कुमारी

इनोवेशन,जॉब क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता: उपमुख्यमंत्री

जयपुर।

इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) ने आज द ललित जयपुर में अपना राजस्थान चैप्टर ऑफिशियली लॉन्च किया,जो राज्य लेवल पर इंडो- यूएस इकोनॉमिक एंगेजमेंट को गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।लॉन्च सेरेमनी में राजस्थान सरकार की माननीय उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में और यूएस एम्बेसी के कमर्शियल अफेयर्स मिनिस्टर काउंसलर जोनाथन हेमर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मौजूद थे और उन्होंने बाइलेटरल रिलेशन में राजस्थान की बढ़ती स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस पर ज़ोर दिया।लॉन्च सेरेमनी की शुरुआत करते हुए, राजस्थान सरकार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दीया कुमारी ने कहा, 'इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स, राजस्थान चैप्टर का शुरुआत होना गर्व और खुशी का पल है और कुछ ऐसा जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। अपनी शुरुआत से ही,आईएसीसी ने भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक एंगेजमेंट को मज़बूत करने, खास सेक्टर्स में ट्रेड,इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।इसके राजस्थान चैप्टर का लॉन्च इस कोलेबोरेशन को स्टेट लेवल तक ले जाने की दिशा में एक अहम कदम है।'

'राजस्थान मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ के साथ तेज़ी से ग्रोथ की कगार पर है।जैसे-जैसे हम विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं, आईएसीसी का लॉन्च ग्लोबल पार्टनरशिप,इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए सही समय पर हुआ है ',उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा।

'आईएसीसी राजस्थान चैप्टर की शुरुआत राजस्थान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक एंगेजमेंट को गहरा करने की दिशा में एक सही समय पर उठाया गया कदम है।राजस्थान चैप्टर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को आसान बनाने,सेक्टर के बीच कोलेबोरेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने, पॉलिसी डायलॉग को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुँचने में सपोर्ट करने के लिए एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा।' उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'राजस्थान सरकार एक ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्टर-फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करने वाली पहलों को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड है।हम इसे सिर्फ एक इकोनॉमिक मौके के तौर पर नहीं, बल्कि इनोवेशन,जॉब क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते के तौर पर देखते हैं।मुझे विश्वास है कि यह चैप्टर सहयोग के नए रास्ते बनाने और दोनों तरफ के बिजनेस के लिए ठोस नतीजे लाने में अहम भूमिका निभाएगा।'

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना- ऑनलाइन आवेदन के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल

यात्रा संचालन समिति की बैठक में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने दिए निर्देश

जयपुर।

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी। शासन सचिवालय में मंगलवार को हुई देवस्थान विभाग की यात्रा संचालन समिति की समीक्षा बैठक में पशुपालन, गोपालन,डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने इसके निर्देश दिए।मंत्री कुमावत ने अधिकारियों को देवस्थान विभाग की पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के लिए निर्देशित किया।तीर्थयात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए देवस्थान मंत्री की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।इसमें कमेटी के अध्यक्ष देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत होंगे,जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह विभाग,अतिरिक्त मुख्य सचिव,अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिव,देवस्थान,शासन सचिव, पर्यटन,प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व आयुक्त,देवस्थान विभाग,उदयपुर को सदस्य बनाया गया है।इस कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को आयोजित की गई।इसमें देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इस बार भी 50 हजार वरिष्ठजनों को वातानुकूलित ट्रेन एवं छह हजार यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

बैठक में देवस्थान विभाग की वर्ष-2026 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।देवस्थान मंत्री ने अधिकारियों को बजट में स्वीकृत योजनाओं और कार्यों को शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि बजट में स्वीकृत कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए।उन्होंने विभाग के अधिकारियों को बजट में स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता पर रखते हुए अपनी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति के निर्देश दिए तथा गत वर्ष की बजट घोषणाओं के कार्य भी शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।मंत्री कुमावत ने कहा कि बैठक के दौरान देवस्थान विभाग के प्रमुख मंदिरों में सुबह-शाम की आरती के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।बैठक में देवस्थान विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी,आयुक्त एलएन मंत्री,अतिरिक्त आयुक्त गितेश मालवीय,शासन उप सचिव आलोक सैनी,एडीसी जयपुर प्रथम रतनलाल योगी सहित आईआरसीटीसी, पर्यटन, चिकित्सा एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की बिजली वितरण निगमों की समीक्षा

डिस्कॉम्स विकसित करेंगे विकेन्द्रित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली

जयपुर।

प्रदेश में डिस्कॉम्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं।इसके अन्तर्गत उन क्षेत्रों में बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली विकसित किए जाने की योजना है,जहां पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों अथवा रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों से प्रचुर मात्रा में सरप्लस विकेन्द्रित सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है।इससे सुबह और शाम के पीक ऑवर्स की विद्युत सप्लाई को मेंटेन करने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार को विद्युत भवन में बिजली वितरण निगमों कंपनियों की समीक्षा के दौरान इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गति देने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि इससे विद्युत आपूर्ति को बेहतर किया जा सकेगा।उन्होंने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टोरेज क्षमता का विस्तार आवश्यक है।शासन सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने बैठक में बताया कि जयपुर,जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा उत्पादित विकेन्द्रित सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडअलोन डिसेन्ट्रलाइज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित किए जाएंगे।

बैठक में ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटरिंग, बिजली छीजत में कमी और गर्मी के दौरान विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की।साथ ही नागर ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटरिंग से उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग मिल रही है।उन्होंने आरडीएसएस योजना में बिजली छीजत कम करने के लिए और प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में तकनीकी और वाणिज्यिक लॉस अधिक हैं,वहां फीडर सुधार और सघन निगरानी की जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 37.81 लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।इसी तरह लॉस रिडक्शन के अन्तर्गत आरडीएसएस योजना में 33 केवी के 179 नए जीएसएस बनाए गए हैं।जिससे संबद्ध क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या दूर हुई है। इसी तरह ट्रिपिंग कम करने तथा लोड बैलेसिंग के लिए 60 प्रतिशत फीडरों का विभाजन किया गया है।बैठक में ऊर्जा विभाग के सलाहकार नवीन अरोड़ा, अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा,तीनों वितरण निगमों के निदेशक तकनीक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ.भंवरलाल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।